योजनाओं को पलीता लगा रहे पंचायती राज के कर्मचारी व अधिकारी

हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने कार्यालयों का लगा रहे चक्कर

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। मध्यप्रदेश की सत्तासीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा जहां पंचायतों के अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने विकास का मार्ग प्रसस्त किया जा रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर बैठे अधिकारियों के उदासीन रवैये से ग्रामीण अंचलों के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास अवरूद्ध है योजनाओं में भ्रष्टाचार का पहरा है। नुमाइंदों से तंत्र का गहरा रिश्ता है जब नेता नेतृत्व की नियत ही तंत्र की मिली भगत से संदेहास्पद एवं पथ भ्रमित हो तो शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाना आसान नहीं।

परिणामस्वरूप योजनाएं नुमाइंदो तक सिमटकर रह जाती है जब योजनाओं सें संबंधित विभागीय अमला योजनाओं के क्रियान्वयन में खुद सौदेबाजी पर उतर आये तो मैदानी कर्मचारी एवं कर्मचारी का क्या कसूर।

एक ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य ने अपने अनुभव को कलमबद्ध करते हुए बताया है कि बच्चों के जन्म से लेकर लालन पालन तक पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी व्याह तक पोथी पत्रा से लेकर साईकिल, ड्रेस भोजन तक जन्मदिन मनाने से लेकर गोद भराई तक की चिंता में गांव-गांव की सुधि लेकर विकास की दिशा और दशा बदलने का संकल्प ले चुके मुख्यमंत्री की योजनाओं को मटियामेट करने धुनलोलुप तंत्र की भ्रष्ट मानसिकता एवं मिल

बांटकर खाने की परंपरा ने सभ्य समाज के सभ्य जनप्रतिनिधियो को भी अपने आगोश में ले लिया है। पंचायत सरपंचों में जहां स्वविकास की होड़ लगी है वहीं दूसरी ओर अनपढ़ अशिक्षित सरपंच, हरिजन आदिवासी महिला पुरूषों को अपने प्राप्त अधिकारों से बंचित होना पड़ा। परिणामस्वरूप आरक्षित पंचायतों में भ्रष्टाचार ने ऐसा पांव पसारा कि शिष्टाचार और ईमानदारी को लकवा मार दिया।

विगत दशकों में शायद ही एक पंचायत ऐसी हो जहां लगभग एक करोड़ की राशि का आबंटन न हुआ हो जबकि इतनी भारी भरकम राशि से गांव सहित ग्रामवासियों का भी कायाकल्प हो जाता। जबकि आज भी जिले के अंतर्गत यदि किसी भी एक पंचायत में हुये कच्चे या पक्के कार्य की वास्तविक जांच हो जाए तो नुमाइंदो सहित अधिकारियों की पोल खुलते देर नहीं लगेगी। खास तौर से पी सीसी रोड ने आज इन रोड़ों का हाल यह है कि कच्ची गलियों से भी बदतर स्थिति है।

मुख्यालय अंतर्गत हुये पीसीसी रोड का निर्माण हो या तालाबों का निर्माण हो जिसका मूल्यांकन उपयंत्रियों ने आंख मूंदकर कर दिया है और अधिकारी है कि उत्कृष्ट विकास का प्रमाण पत्र देकर सराकर से झूठी वाहवाही लूट रहे है। यह केवल रोड़ की समस्या नहीं है बल्कि कपिलधारा अंतर्गत हुए कूप निर्माण के हश्र को भी देखा जा सकता है। मेड़ बंधान बृक्षारोपण, तालाबों का गहरीकरण हो या बीस से पचास लाख तक की लागत से बनाया गया तालाब हो। जाहिर है शासन की राशि को कागजी जामा पहनाकर शासन को भारी पैमाने पर आर्थिक क्षति पहुंचने एवं विकास के नाम पर शासन को भी गुमराह करने का कूटरचित प्रयास किया गया जिससे मुख्यमंत्री के नीति एवं नियति पर संदेह की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। योजनाओं के इस दुर्दशा मे अहम भूमिका निभाने में उपयंत्रियां, अधिकारियों, सचिवों, सरपंचो, दलालों ने मुख्य भूमिका निभाकर गांवो के विकास को 20 वर्ष पीछे ढकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

बंदियों का किया स्वास्थ्य परीक्षण विधिक अधिकारों की दी जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरतचन्द्र सक्सेना के मार्गदर्शन में रविवार को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला जेल पन्ना में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराईं। टीम द्वारा बंदियों का चिकित्सकीय परीक्षण कर आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाईयों का वितरण किया गया। बंदियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित आहार के उपयोग एवं व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव व समझाईश दी गई। जेल में निरूद्ध बंदियों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर भी लगाया गया। इस दौरान व्यवहार न्यायाधीश राजकुमार गौड़ ने विचाराधीन बंदियों के जमानत आदेश तथा समस्याओं के निराकरण पर चर्चा कर उचित माध्यम से विभिन्न आदेश का क्रियान्वयन कराने का आग्रह किया। जेल मैनुअल अनुसार बंदियों को मूलभूत सुविधाओं के प्रदाय के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा बंदियों के प्रकरणों की जानकारी लेकर विभिन्न उपयोगी विधिक प्रावधान बताए गए।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के जरिए प्रकरणों में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की सलाह भी दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट बिन्दु पटेल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा भी कानूनी प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी से अवगत कराया गया। आनंद त्रिपाठी एवं अधिवक्ताओं द्वारा नि:शुल्क अपील का अधिकार, लोक अदालत की उपयोगिता, मध्यस्थता के लाभ इत्यादि विषयों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधि के तहत संगीत एवं गायन भी हुआ, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

महावीर जयंती पर अवकाश 31 मार्च के स्थान पर आज

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। कलेक्टर पन्ना श्रीमती उषा परमार ने मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 मार्च को दिये गये निर्देशानुसार महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च के स्थान पर 30 मार्च को अवकाश घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जैन समाज पन्ना द्वारा भी पन्ना जिले में 30 मार्च को ही महावीर जयंती मनाई जा रही है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर पन्ना द्वारा 31 मार्च के स्थान पर आज 30 मार्च सोमवार को महावीर जयंती पर अवकाश रहेगा। 31 मार्च मंगलवार को सभी शासकीय कार्यालय यथावत खुलेंगे।

क्षत्रसाल कालेज में आपदा प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण

एमएस डब्ल्यू व बीएसडब्ल्यू के छात्रों ने लिया भाग

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। पीएम श्री छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में रविवार को आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय में संचालित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जिला सेनानी होमगार्ड शालिवाहन पांडेय ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भूकंप, बाढ़ जैसी अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बिना पूर्व सूचना के आती हैं, इसलिए सतर्कता और पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को आपदा के समय सही निर्णय लेने, स्वयं सुरक्षित रहने तथा राहत एवं बचाव कार्यों में प्रभावी सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में उपस्थित परामर्शदाताओं एवं छात्र-छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता करते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।

जिले में 9 शराब दुकानों के हुये टेंडर, अब सिर्फ 7 दुकानें शेष

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति के अंतर्गत पन्ना जिले में शराब दुकानों के ई टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक आठ चरण संपन्न हो चुके है। जिसमें 39 शराब दुकानों में से 32 शराब दुकानों का निष्पादन हो चुका है शेष मदिरा दुकानों में पवई समूह में शराब दुकान पवई और कृष्णगढ शेष है।

एकल दुकान समूहों में गुनौर, सलेहा, देवेन्द्रनगर, अजयगढ़ और मोहन्द्रा शेष है। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि ई टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया के आठवें चरण में 6 समूहों में 15 शराब दुकानें नीलामी के लिए ई-टेंडर ऑनलाइन लाइव किए गए थे । इस चरण में समूहों के साथ ही सिंगल शराब दुकान भी टेंडर के लिए लाइव की गई थी। सिंगल दुकान होने से इस चरण में नीलामी की प्रक्रिया ठेकेदारों के लिए आकर्षित हो गई थी। जिसकी वजह से कुल 15 दुकानों के लिए 20 ई टेंडर प्राप्त हुए थे। जिसमें 3 ई टेंडर रैपुरा समूह के लिए भी प्राप्त हुए। इस समूह में शराब दुकान रैपुरा और बघवार कला शामिल है। शासन द्वारा 15 प्रतिशत कम राशि तक के ई टेंडर आमंत्रित किए थे।

शराब दुकान समूहो के टेंडर - रैपुरा समूह के लिए 14 करोड़ 24 लाख 84 हजार 831 रुपए के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध 6.8 प्रतिशत कम की राशि 13 करोड़ 28 लाख का ई टेंडर प्राप्त हुआ । एकल दुकान मुड़वारी के आरक्षित मूल्य 1 करोड़ 70 लाख 22 हजार 293 रुपए के विरूद्ध 15 प्रतिशत कम राशि 1 करोड़ 44 लाख 68 हजार 951 रुपए का ई टेंडर प्राप्त हुआ। एकल दुकान बराछ की आरक्षित मूल्य 2 करोड़ 9 लाख 98 हजार 955 रुपए के विरुद्ध 29.53 प्रतिशत बढकर 2 करोड़ 71 लाख 99 हजारए 999 रुपए का उच्चतम ऑफर ई-टेंडर कम ऑक्शन में प्राप्त हुआ है। शराब दुकान पटना तमोली के आरक्षित मूल्य 2 करोड़ 92 लाख 27 हजार 696 रुपए के विरुद्ध 20.43 प्रतिशत बढकर 3 करोड़ 51 लाख 99 हजार 999 रुपए का टेंडर प्राप्त हुआ है। शराब दुकान सुपंथा कटन के आरक्षित मूल्य 2 करोड़ 11 लाख 13 हजार 368 के विरुद्ध 14.75 प्रतिशत कम मूल्य पर 1 करोड़ 79 लाख 99 हजार 999 रुपए का ई टेंडर प्राप्त हुआ। शराब दुकान सुंदरा के आरक्षित मूल्य 1 करोड़ 41 लाख 69 हजार 219 रुपए के विरुद्ध 21.39 प्रतिशत बढकर 1 करोड़ 71 लाख 99 हजार, 999 रुपए का उच्चतम ऑफर ई-टेंडर कम ऑक्शन में प्राप्त हुआ।

शराब दुकान सिंहपुर के आरक्षित मूल्य 2 करोड़ 6 लाख 41 हजार 678 रुपए के विरुद्ध 14.74 प्रतिशत कम राशि 1 करोड़ 75 लाख 99 हजार 999 रुपए प्राप्त हुआ। उक्त सभी मदिरा दुकानों के ऑफर मूल्य को स्वीकृत करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इन सभी दुकानों का कुल मूल्य 26 करोड़ 24 लाख 68 हजार 946 रुपए है। शराब दुकान हरदुआ पटेल के आरक्षित मूल्य 2 करोड़ 27 लाख 97 हजार 963 के विरुद्ध ई-टेंडर कम ऑक्शन पर बोली चल रही थी तभी एमपी टेंडर पोर्टल की वेबसाइट क्रैश हो गई जिससे नीलामी प्रक्रिया बाधित हुई है। तकनीकी सुधार तक नीलामी प्रक्रिया स्थगित है। शेष दुकानों पवई समूह, शराब दुकान गुनौर, सलेहा, देवेंद्रनगर, अजयगढ़ और मोहन्द्रा के ई-टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया हेतु टेंडर एमपी टेंडर पोर्टल पर लाइव कर दिए गए है। शेष शराब दुकानों पर सरकार द्वारा 20 प्रतिशत कम तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। अभी तक पन्ना जिले में 92 करोड़ 39 लाख 83 हजार 11 रुपए का राजस्व शेष है। इच्छुक टेंडर दाता आबकारी पोर्टल में ऑनलाइन कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन करवा कर ऑनलाइन टेंडर डाल सकते है।

क्वालिटी कंट्रोल पर निर्माण विभागों का नहीं है नियंत्रण

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। सरकारी विभागो में निर्माण में अब घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं हो पायेगा। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग का गुणवत्ता परिषद गंभीरता से विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सामग्री जांच के मामले में निर्माण विभागों को पूर्व में कई बार आदेश व निर्देश भी दिये

गये कि उन्हें सामग्री की जांच कहा से कितनी और कैसे करवानी है। किन्तु निर्माण एजेंसियों ने अपनी सुविधा के अनुसार ही सामग्री जांच की खानापूर्ति की। यही कारण है कि कई कार्य घटिया एवं अमानक सामग्री के उपयोग के कारण गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार तैयार नहीं हो पाये। किन्तु शायद अब ऐसा नही हो पायेगा। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रयोगशालाओं की छानबीन एवं पड़ताल शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में सभी निर्माण विभागों को पत्र जारी कर प्रयोगशालाओं की जानकारी चाही गई है।

जीएडी ने मांगी थी जानकारी:- निर्माण विभागों से पूर्ण हुये कार्यो के संबंध में सामग्री की जांच किन प्रयोगशालाओं से करवाई गई इसकी जानकारी जीएडी ने मांगी थी किन्तु क्या हुआ आज तक पता नहीं चल पाया।

संबंधित विभागों से इस आशय की जानकारी चाही गई है कि जो निर्माण कार्य करवाये गये हैं उनमें उपयोग होने वाली सामग्री की जांच किन प्रयोगशालाओं से करवाई गई है इसकी जानकारी संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही विभागों को प्रयोग किये जा रहे उपकरणों की भी जानकारी देनी होगी। सभी निर्माण विभागों को प्रयोगशालाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

प्रयोगशालाओं में कई प्रकार की जांच

निर्माण कार्यो में उपयोग की जाने वाली सामग्री की जांच प्रयोगशालाओं से करवाई जाती है। इस तरह की प्रयोगशालाओं के लिये जरूरी है कि उन्हें विभागीय स्तर से मान्यता होनी चाहिये। प्रयोगशाला विभागीय है, कन्सल्टेन्ट की प्रयोगशाला है, ठेकेदार की प्रयोगशाला है, एनएबीएल की प्रयोगशाला है अथवा निजी प्रयोगशला है इन सभी तरह की प्रयोगशालाओं की जानकारियां चर्चा में आती रहती हैं। किन्तु देखा जाता है कि शासकीय निर्माण विभागो में सामग्री जांच के नाम पर औपचारिकता अधिक होती है। यही कारण है कि घटिया स्तर की सामग्री को भी प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बता दिया जाता है।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता एवं समरसता रथ यात्रा आज

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। रंजोर सिंह पटेल जिला अध्यक्ष एवं राम भगत पटेल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुर्मि क्षत्रिय समाज के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरदार पटेल एकता रथ 30 मार्च को दोपहर 12 बजे पन्ना नगर में पहुंचेगी। यह रथ यात्रा गुजरात राज्य से चलकर मध्य प्रदेश में कई जिलों से गुजरने के पश्चात पन्ना आ रही है।

यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, सरदार पटेल के सपनों का भारत जिसमें भारतीय समाज में भाईचारा, आपसी सहिष्णुता, सौहार्द, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह रथ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा है। इस रथ का पन्ना नगर में 12 बजे सत्यम पैलेस में स्वागत सत्कार के पश्चात रथ यात्रा नगर भ्रमण करेगी जिसमें क्रमश: डायमंड चौक, ब्लॉक तिराहा, बीटीआई चौक, कोतवाली चौराहा, छत्रसाल पार्क, बलदेव मंदिर चौक, बड़ा बाजार चौराहा, अजयगढ़ चौराहा, पुरानी कोतवाली, गांधी चौक, पुराना पावर हाउस होते हुए मोहन राज विलास होटल पन्ना में रैली का मंचीय कार्यक्रम एवं समापन होगा। उक्त रथ में तीन किलोग्राम सोने का स्तूप, सरदार पटेल के कारावास के समय की टिफिन पेटी , राजाओं द्वारा दिये गये विलीनीकरण के पत्र एवं उनकी चरण पादुका का आमजन के दर्शनार्थ रखें गए है।

दक्षिण वनमण्डल में टेलीस्कोपिक रेक्स एवं जनजागरूकता अभियान

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। दक्षिण पन्ना वनमण्डल में वन अग्नि की घटनाओं को नियंत्रित रखने हेतु ग्रीष्मकाल एवं महुआ संग्रहण के मौसम को ध्यान में रखते हुए टेलीस्कोपिक रेक्स का उपयोग, सतत निगरानी गश्त तथा जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से आग की घटनाओं को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कल्दा वन परिक्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी परिवेश सिंह भदौरिया के निर्देशन में वन अमले द्वारा महुआ बाहुल्य क्षेत्रों में टेलीस्कोपिक रेक्स का प्रयोगात्मक वितरण किया गया है। इन रेक्स के माध्यम से महुआ वृक्षों के नीचे जमा सूखी पत्तियों (लीफ

लिटर) को बिना आग लगाए हटाया जा सकता है, जिससे आग लगने की संभावनाएं कम होंगी। शाहनगर वन परिक्षेत्र में बीट बोरी, बिसानी, उमरिया एवं ताला क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता एवं गश्ती गतिविधियां संचालित की गई। बीट बोरी में बस स्टैंड एवं पुलिस चौकी पर ग्राम वन समिति महेबा के अध्यक्ष भूरा बंजारा तथा बीट गार्ड प्रेम नारायण वर्मा द्वारा ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा संबंधी समझाइश दी गई एवं पोस्टर-बैनर लगाए गए। सर्किल बिसानी एवं बीट उमरिया में परिक्षेत्र सहायक अनिल प्रताप सिंह तथा वनरक्षक आशीष पाण्डेय द्वारा वन भ्रमण एवं प्राकृतिक जलस्त्रोतों का निरीक्षण किया गया।

रैपुरा, पवई एवं मोहन्द्रा वन परिक्षेत्रों में भी वन अग्नि नियंत्रण हेतु विशेष गश्त एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की गई। रैपुरा क्षेत्र में परिक्षेत्र सहायक रंजना नागर एवं वनरक्षक बद्री प्रसाद यादव एवं सर्किल घुटेही के सदस्यों द्वारा संयुक्त रात्रि गश्त कर वन सीमा, शिकार संभावित स्थलों, जलस्त्रोतों एवं विद्युत लाइनों का निरीक्षण किया गया। पवई वन परिक्षेत्र में रेंज ऑफिसर नितेश पटेल के निर्देशन में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता बैनर लगाए गए। वहीं मोहन्द्रा वन परिक्षेत्र में वनरक्षक राजू अहिरवार द्वारा जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया तथा बीट गार्ड पश्चिमी मोहन्द्रा जगदीश प्रसाद अहिरवार एवं बीट गार्ड बिलपुरा हरप्रसाद अहिरवार द्वारा विशेष गश्त कर अग्नि नियंत्रण के प्रयास किए गए।

छात्रावासों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह, सही मॉनीटरिंग न होने से व्यवस्थाएं चरमराई

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों मे संचालित छात्रावासों में लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी छात्रावासों की सुरक्षा मे संबंधित विभाग लापरवाही बरत रहा है।

स्थिति यह है कि छात्रावासों की समय समय पर जांच पड़ताल नहीं हो रही है। जिससे यहां संचालित होने वाली गतिविधियों का भी पता नहीं चल पाता है। छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर शासन की ओर से 30 पैरामीटर भी बनाए गए हैं। लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। अधिकांश छात्रावासों मे आगुतुक रजिस्टर भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल सेल्टर होम में हुई घटना के बाद समूचे प्रदेश भर के छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिये गये थे। लगातार घटनाओं के बाद छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कतई गंभीर नहीं है। इसका पालन कराने में जिम्मेदार अफसरों का पसीना छूट रहा है। हकीकत का पता नहीं चल पाता है। जिलेभर में आदिम जाति कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग, सर्वशिक्षा केंद्र, रमसा विभाग की ओर से लगभग एक सैंकड़ा बालक व बालिका छात्रावास का संचालन किया जा रहा हैं। इनमें से अधिकांश छात्रावासों में कैमरे ही नहीं लगे हैं। जिम्मेदारी की लापरवाही का आलम यह है इनमें से एक भी छात्रावासों में कैमरे ही नहीं लगे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास की स्थिति यह है कि इन छात्रावासों मे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है।

स्कूलों में ही बनेंगे और अपडेट होंगे आधार कार्ड

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार शिविर का अगला चरण एक अप्रैल से शुरू किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विद्यालय परिसर में ही आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें नामांकन और अपडेट के लिए अलग से कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। विद्यार्थियों के लंबित बायोमैट्रिक अपडेट को पूर्ण करने के उद्देश्य से अभियान का अगला चरण प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 मई तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर ही आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। आधार शिविरों के कुशल संचालन के लिए ऑपरेटर्स का चयन किया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में शालाओं के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित भी किया गया है कि वे यूडीआईएसई प्लस पोर्टल से उन विद्यार्थियों की सूची अद्यतन कर लें, जिनके आधार में एमबीयू पेंडिंग हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आधार अपडेट कराने के लिए जागरूक करें और इसके लिए एक रोस्टर बनाएं। स्कूल शिक्षा विभाग की यह पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट पर केन्द्रित है, जिसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आइरिस स्केन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। पहला अपडेट तब आवश्यक है, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए। दूसरा एमबीयू तब आवश्यक है, जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाए। दूसरा एमबीयू 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच पूरा होने पर नि:शुल्क है, लेकिन 17 वर्ष की आयु के बाद शुल्क लागू होता है। अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाला आधार कार्ड, स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अपार आईडी विद्यार्थियों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और सह पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करती है। यह आईडी शिक्षा जगत में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है।

गैस की किल्लत के चलते बढ़ी इंडक्शन की कीमतें, भारी संख्या में इंडक्शन की हुई बिक्री

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 मार्च। ईरान और अमेरिका व इजरायल के युद्ध के कारण चल रही गैस की किल्लत और उसके सोशल मीडिया पर प्रचार के कारण लोगों में भयावह माहौल बना हुआ है। जिसके कारण लोगों ने गैस का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था। इसमे सबसे अच्छा विकल्प इंडक्शन चूल्हा लोगों की समझ में आया और उसकी खरीदारी बढ़ गई।

खरीदी बढने से जहां बाजार में अधिकतर दुकानों पर इंडक्शन चूल्हा मिल ही नहीं रहा है, तो कई दुकानों पर कीमत बढ़ाकर बेचा जा रहा। गैस सिलेंडरों की किल्लत का असर अब रसोई के विकल्पों पर भी दिखाई देने लगा है, जिससे लकडी कण्डे, कोयला व कैरोसिन से ज्यादा अच्छा विकल्प इंडकन चूल्हा ही दिखाई दे रहा है। वहीं इस मामले में बिजली की खपत से अधिक लोग परेशानी से बचाव को दे रहे हैं।

गैस की आपूर्ति को लेकर जमीनी हकीकत चाहे जो भी लेकिन प्रशासन और सरकार के ऑल इज वेल के दावे के बावजूद जनता इस परेशानी से बचना चाह रही है। ऐसे में लोग बिजली से चलने वाले इंडशन चूल्हों की ओर रूख कर रहे है। विगत कई दिनों में बाजार में इंडशन चूल्हों की खरीद हो रही है, जिसके तहत यह आमतौर पर अधिकतर कम्पनी के इंडशन चूल्हे 2000 से लेकर 4000 रूपये तक मिल रहे हैं। वहीं उसमें और अच्छी क्वालिटी वाले महगे भी आ रहे हैं। ऑनलइन खरीद पर दामों में कमी आने के कारण लोगों ने वहां का रूख किया।

स्थिति यह रही कि ऑनलाइन मार्केट यानी ई मार्केट प्लेस पोर्टलों पर इंडक्शन चूल्हों की खरीद इतनी बढ़ गई है कि कई प्लेटफार्म पर ये आउट ऑफस्टॉक हो गए है, जबकि शहर की इलेट्रानिक दुकानों पर भी इनकी बिक्री में अचानक तेजी आ गई है।

घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी से परेशान हैं उपभोक्ता:- इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे आम नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि कई बार प्रयास करने के बावजूद उनकी बुकिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है।

रेस्टोरेंट एवं होटलों में कैसे पहुंच रही है घरेलू सिलेंडर

आम आदमी को घरेलू सिलेंडर लाइन लगाने के बाद भी मुश्किल से मिलती है लेकिन शहर के रेस्टोरेंट एवं होटलों में घरेलू सिलेंडर का पर्याप्त भंडारण है। जिम्मेदार खाद्य अधिकारी एवं एसडीएम तथा अन्य जिम्मेदार निरीक्षण नहीं करते हैं। जिस वजह से हालात यह है कि भले ही कामर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है परंतु शहर के घरेलू सिलेंडर का उपयोग आधी रात को गैस एजेंसी वाले होटलों में पहुंचाते हैं। निरीक्षण हो तो सच्चाई का खुलासा हो सकता है लेकिन खाद्य अधिकारी द्वारा इस मामले में काइे पहल नहीं की जा रही है।